

सिंगल कॉलम

60 हजार किलो से ज्यादा वजन रखकर किया मेट्रो ट्रैक का लोड टेस्ट

इंदौर। इंदौर में मेट्रो के लिए गांधी नगर से लेकर रेडिसन होटल तक मेट्रो ट्रैन का ट्रैक तैयार हो चुका है। पांच स्टेशन भी तैयार हो रहे हैं। ट्रैक पर परिवर्तन भी बिल्डई जा चुकी हैं। अब मेट्रो ट्रैन का पारियार से बुधवार से ट्रैक का लोड टेस्ट शुरू किया। इसके लिए विशेष क्रोंक का उपयोग किया जा रहा है। उसकी मदद से ट्रैक पर ब्लॉक रखे गए। 60 हजार किलो से अधिक वजन रखकर मेट्रो ट्रैक कितना वजह सह सकता है। इसे अफसर परख रहे हैं। इसके लिए ट्रैक के नीचे उपकरण भी लगाए गए हैं। मंगलवार से लोड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। वजनी ब्लॉक के अलावा रेट की बोरिंग रखकर एमएस-10 ब्रिज के समीप लोड टेस्ट शुरू हुआ। बुधवार दोपहर तक तय क्षमता के अनुसार वजन ट्रैक पर रखा गया। ट्रैक के नीचे डॉयल गेज लगाया गया था। वजन रखने के बाद उस पर पिलर के झुकाव की स्थिति देखी गई। लोड टेस्ट के लिए भोपाल से टीम आई थी। अब इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। जिसे कमिशनर आर. मेट्रो रेल सेफ्टी को सौंपी जाएगी। इसके बाद ट्रैक को कमर्शियल रन के लायक माना जाएगा। ट्रैक के कुछ अन्य हिस्सों में भी इस तरह का लोड टेस्ट हो सकता है। आगे वर्ष तक अफसरों ने कमर्शियल रन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। पिलाहाल मध्य हिस्से में मेट्रो ट्रैक का काम शुरू नहीं हो पाया है।

सफाई नहीं मिली तो दरोगा का वेतन काटा, एनजीओ पर भी लगाई पैनलटी

इंदौर। इंदौर को उन्वें नेशनल बाटर अवॉर्ड में वेस्ट जोन की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया गया। जिसमें वर्षा बुधवार सुबह से एक्शन में आ गए। उन्होंने बिलबाली, लिंबोदी तालाब का निरीक्षण किया और कान्ह नदी के शुद्धिकरण की रिपोर्ट ली। इसके बाद वर्षा बार्ड क्रायपक 75 में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। वार्ड में गंदगी पाए जाने पर दरोगा अरुण सेन का पांच दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने एनजीओ फोडबैक के दौरान अपर आयुक्त रोहित सिंहानिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा मुमूक्षु ने इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिशनर शिवम वर्मा का अवॉर्ड से सम्मानित किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर में जल संरक्षण की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों की कई नियंत्रित किया जा रहा है। कई माध्यमों से जल संरक्षण किया जा रहा है। अवॉर्ड प्राप्ति के बाद नगर निगम तेजी से एक्शन में आ गया है। ग्राम पंचायत वार जीआईएस आधारित योजना तैयार बनाई गई।

कन्फेक्शनरी कारोबारी की पुलिस से शिकायत करने दिल्ली से आए व्यापारी

इंदौर। दिल्ली के तीन व्यापारियों ने बुधवार को इंदौर के एक व्यापारी की पुलिस कमिशनर से शिकायत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि यहां के कन्फेक्शनरी कारोबारी ने हमारे साथ तीन कोडे की धोखाधड़ी की है। इस संबंध में तीनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला इंदौर के कारोबारी गोरख अहलावत से जुड़ा है। बुधवार को दिल्ली के व्यापारी छोटेलाल पुरी ने पुलिस से शिकायत की। तीनों ने आयोग लगाया कि अहलावत ने रशया की नागरिकता ले रखी है। वो हमें वहां को सकारा द्वारा कार्रवाई किए जाने के नाम से डरता है। अहलावत ने कुछ साल पहले अपनी दिल्ली स्थित कंपनी जीआईपी क्रिएशंस के लिए प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम कराया था, जिसके एवज में 50 लाख रुपए देना थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं दिए। इसके बाद उन्होंने फोन उत्तरा ही बंद कर दिया। देनदारी से बचने के लिए अपना पता भी कबूल दिया गया। एक अन्य व्यापारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मेरी फर्म प्राची प्रिंट एंड पैकेजिंग से अहलावत ने प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम करा कर 21 लाख रुपए नहीं चुका।

लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के पास तीन भुजा के ओवरब्रिज का काम शुरू

इंदौर। दोर में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास रेलवे ब्रिज का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए निर्माण एजेंसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीडल्यूडी ने बुधवार से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के पास स्थित माल गोदाम रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। क्रॉसिंग पर तीन भुजा वाले ब्रिज का निर्माण किया जाना है। क्रॉसिंग नंबर 243 पर काम शुरू करने के लिए रियल कस्ट्रक्शन कंपनी ने बैरिकेट्स लगा दिए हैं। वाहन चालक अब पोलो ग्राउंड अंडर ब्रिज या बाणीगंगा क्रॉसिंग पर होते हुए आना-जाना सर कंकें। माल गोदाम क्रॉसिंग ओवरब्रिज के निर्माण पर पीडल्यूडी करीब 29 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और इस दूलेन चौड़े ब्रिज का निर्माण डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

इंदौर शर्मसार... सड़क पर रातभर नन भटकती रही रेप पीड़िता

सिटी चीफ इंदौर।
इंदौर। इंदौर में एक हैवानियत भरी घटना सामने आई है। एक युवक ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला का रेप कर उसे अर्धनग्न हालत में सड़क पर छोड़ दिया। महिला रातभर शहर की सड़कों पर धूमती दिखी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल, घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के नीलकंठ कॉलोनी की है। सड़क पर मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला अर्धनग्न हालत में धूमती दिखी।



साल की मानसिक रूप विक्षिप्त महिला सड़क पर धूम रही थी। महिला को युवक महिला को अकेला धूमता देख वहां से गुजर रहा

उसे अर्धनग्न हालत में छोड़ दिया।

आरोपी ने जर्म कबूल।

एडीसीपी के मूलविक आरोपी सोनू पेशे से हम्माल है। वह मूल रूप से सागर का रहने वाला है। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की है। दूसरी ओर आरोपी ने भी दुष्कर्म करने की बात कबूल की है। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

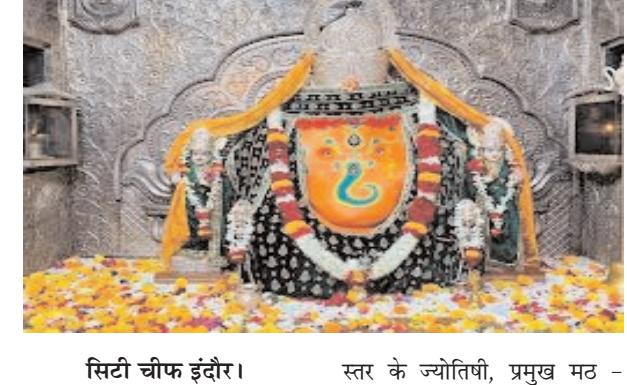
पुलिस ने पहाना कपड़े।

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी महिला के साथ जाता हुआ दिखाइ दे रहा है। तब उसके बदन पर कपड़े थे। दुष्कर्म के कुछ देर बाद महिला अर्धनग्न हालत में नीलकंठ

कॉलोनी में धूमती हुई दिख रही है। सुबह कीरब 4 बजे सफाईकर्मियों ने जब महिला को देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने महिला की तो महिला कीरब 4.30 बजे एक गाड़न के पास बैठी मिली, जिसके बाद उसे कपड़े पहना और पूछताल की, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी।

खाली टप्पे में ले गया था आरोपी खाली टप्पे में लेकर गया था। घटनास्थल के आसपास पुलिसकर्मियों के मकान हैं। एक चौकीदार का परिवार भी रहता है। यहां से महिला कीरब आधा किलोमीटर तक बिना कपड़ों के पैदल गई थी। आसपास रहने वालों के मुताबिक उहाने कुछ नहीं देखा।

खजराना गणेश मंदिर में दीवाली 1 नवंबर को, यह शास्त्र सम्मत



सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। दीवाली इस बार 31 अक्टूबर या एक नवंबर को मनाए जाने को लेकर सभी पंडित अपने-

-अपने तर्क दे रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी विनीत भट्टट ने बताया कि मंदिर में 1 नवंबर को दीवाली मनाई जाएगी। भट्टट ने कहा कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, सौंस दें आधिक पंचांगों आदि ग्रन्थों का धर्म मत है कि जब प्रदोष काल में अमावस्या आती हो तब उसी दिन को मनाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है। इसी दिन हमारा पितृ कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इस दिन शाम 6.18 बजे तक अमावस्या रहेगी।

भट्टट ने आगे कहा कि इस दिन स्वाति नक्षत्र का भी योग है।

आयोग ने बताया कि इन सभी मंदिरों ने भी शास्त्र सम्मति को मनाने का नियम दीवारी द्वारा रखा है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के सामने सावधानीकृत रूप से इंदौर के बाजार के अपसरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बताया कि इन सभी मंदिरों में होमन यादव के अपसरों पर रहता है।

प्रदेश की अधिकारी ने बत

संपादकीय

मोदी और जिनपिंग की मुलाकात अच्छी बात... लेकिन सतर्कता जरूरी

ब्रिक्स का बैठक के बाद पोएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों के बीच यह वार्ता पांच साल बाद हुई है। मोदी-जिनपिंग के बीच बैठक ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही भारत-चीन ने पूर्वी लद्धाख में एलएसी पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त के समझौते पर सहमति जताई। चार साल से चल आ रहे इस गतिरोध को खत्म करने की दिशा में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है।

प्रधानमंत्रा नरद्र मादा रूस दार पर ह। बुधवार का पाएम न कजान में ब्रिक्स समिति को संबोधित किया। ब्रिक्स की बैठक के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों के बीच यह वार्ता पांच साल बाद हुई है। मोदी-जिनपिंग के बीच बैठक ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही भारत-चीन ने पूर्वी लद्धाख में एलएसी पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त के समझौते पर सहमति जताई थी। चार साल से चल आ रहे इस गतिरोध को खत्म करने की दिशा में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह कोई महज संयोग नहीं कि भारत और चीन रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पूर्वी लद्धाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त लगाने पर एक समझौते पर पहुंचे हैं। इस निर्णय के गहरे कूटनीतिक व सामरिक निहितार्थ हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने पहुंचे। कहना गलत न होगा कि सीमाना विवाद से जुड़े इस फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत के लिए यह मंच तैयार किया गया था। यह एक हकीकत है कि जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में एक बर्फ सी जम गई थी। यहां तक कि दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत करने से भी परहेज कर रहे थे। बहरहाल, गलवान संघर्ष के चार साल बाद आखिरकार दोनों देशों के पास दुनिया को कुछ सकारात्मक दिखाने को तो है। वैसे भी इस गतिरोध के चलते एक बेहद जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में दोनों देशों की सेनाओं को चौबीस घंटे तैयार रहने की स्थिति में नजर आना पड़ता था। इसके अलावा इस घटनाक्रम से यह संदेश भी दुनिया में जाएगा कि दोनों देश बातचीत के जरिये अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। यह घटनाक्रम उस विश्वास को भी मजबूती दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग यूक्रेन-रूस संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। वैसे यह उम्मीद करना जल्दबाजी ही होगी कि भारत-चीन सीमा पर जमीनी हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। भारत को भी गहरे तक इस बात का अहसास है कि बीजिंग को सीमा समझौतों की अवहेलना करने की आदत है। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हालिया फैसले का भी ऐसा ही कोई हश्श हो। ऐसे में भारत को फूंक-फूंककर कदम रखने की जरूरत है। वर्ही दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में तेजी से आ रहे बदलावों और महाशक्तियों के निरंकुश व्यवहार के चलते दुनिया फिर दो ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है। यहं पर वजह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग ब्रिक्स समूह को ताकतवर बनाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इस संगठन में नए देशों को शामिल करने की कवायद लगातार जारी है। बहरहाल, चीन की हालिया सकारात्मक पहल के बावजूद भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। अतीत में चीन भारतीय सीमाओं में अतिक्रमण की कोशिश करता रहा है। गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा यथास्थिति में एकतरफा बदलाव से ही इस विवाद ने तूल पकड़ा। उसके बाद भारत ने सैन्य व राजनीतिक वार्ताओं के जरिये इस विवाद को दूर करने का भरसक प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद डेपसंग और डेमचोक के टकराव वाले बिंदुओं से चीनी सैनिकों की वापसी नहीं की गई।

दुनिया को हैरान करेगी भारत-चीन और रूस की तिकड़ी!

भारत और चीन एशिया की दो महासक्तियां हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से रूस का मोहब्बंग हो चुका है। रूस एशिया की तरफ देख रहा है। उसने चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत कम समय में मजबूत किया है।

भारत-रूस की दोस्ती पुरानी है। अब
रूस का प्रयास है कि दोनों दोस्त साथ
आकर काम करें और यह तिकड़ी पूरी
दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है।
पुतिन जानते हैं कि अगर चीन के साथ
भारत का जमीनी विवाद सुलझ जाएगा
तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। साथ
ही पश्चिमी देशों के लिए यह बहुत बड़ा
दारवाना रहेगा।

एशिया के दो बड़े देश हैं चीन और भारत।



ता इनस बड़ा महाराष्ट्र का पूरा दुनिया में नहीं होगी, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनका एक मंच पर आना असंभव तो नहीं लेकिन आसानी से संभव भी नहीं है। बीते दो दिनों में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। वो यह कि चीन और भारत के बीच मतभेदों को दूर करने की कवायद की जा रही है। इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को भी मिले हैं। यह सब उस वक्त हो रहा है जबकि रूस में ब्रिक्स समिट चल रही है। पीएम मोदी रूस में हैं। वे रूस के कजान शहर पहुंचे ही थे कि चीन ने भी भारत की बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि पूर्वी लद्धाख पर एलएसी विवाद पर हम अपनी पुरानी स्थिति पर लौटेंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस दोस्ती के पीछे रूस है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ही चीन पर दबाव बनाया है तभी चीन माना होगा। जब तक हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक हम इसका दबाव नहीं कर सकते, लेकिन यह एक्सपर्ट्स का अपना एक ओपिनियन हो सकता है। अब ब्रिक्स समिट से एक और तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर अपने ऐप में एक कहानी बयां कर रही है। कोई तस्वीर आजीवन के लिए अमित हो जाती है। ऐसी तस्वीरों को हम लोग ऐंतहासिक शब्द देते हैं। ब्रिक्स समिट के दौरान डिनर का आयोजन किया गया। डिनर पर ही म्हूंजिकल शो भी था। जब भी इस तरह के वैश्वक आयोजन होते हैं तो इसमें बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। कौन-नेता कहां बैठेगा, किस तरफ बैठेगा इन सब

बात का बहुत हा बाराका स परखा जाता है। डिनर के दौरान बीच में रस्स के राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं। उनके एक तरफ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए हैं। हो सकता है कि यह तस्वीर बाकी देशों के लिए कोई खास न हो मगर जो तीन नेता इसमें शामिल हैं उन देशों के लिए यह बेहद खास है। किसी से यह बात छिपी नहीं है कि दशकों से चीन और भारत के संबंध कैसे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्धाख को चीन अपनी सरजमी कहता है। यहां के गांवों को वो अपने नाम दे देता है। भारत अगर वहां विकासकार्य कराता तो चीन बयानबाजी करता है। 1962 में हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा देकर उसने हमारे साथ विश्वासघात किया था। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। दहशतगर्दों के लिए जनत की तरह यह देश भारत को अस्थिर करने में लगा रहता है। चीन उसका साथ सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि वो भारत का दुश्मन है। चीन पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है।

इतनी सारी असहजताओं के बावजूद अगर ब्रिक्स समिट के दौरान बीच में पुतिन और अगल बगल भारत और चीन के नेता मौजूद हैं तो ये बड़ी बात है। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां हैं। रस्स-यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से रस्स का माहूरभंग हो चुका है। रस्स एशिया की तरफ देख रहा है। उसने चीन के साथ अपने रिस्तों को बहुत कम समय में मजबूत किया है। भारत-रस्स की दोस्ती पुरानी है। अब रस्स

का प्रयास है कि दाना दास्त साथ अकरु
काम करें और यह तिकड़ी पूरी दुनिया को
हैरान करने के लिए काफी है।
पुतिन जानते हैं कि अगर चीन के साथ
भारत का जमीनी विवाद सुलझ जाएगा तो
उनके लिए भी फायदेमंद होगा। साथ ही
पश्चिमी देशों के लिए यह बहुत बड़ा झटका
होगा। इन सब चर्चाओं को करते हुए हम
पाकिस्तान को अभी छोड़ देते हैं। इधर मैं
एस जयशंकर की बात का जिक्र करूँगा
एस जयशंकर की छवि पूरी दुनिया में एक
तेज तरार नेता की बनी हुई है। ऐसा मैं नहीं
बल्कि दुनिया के तमाम नेता कह चुके हैं
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक
पॉम्पियो ने अपनी किताब ‘नेव्हर गीव एन
इंच = फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव’
में एस जयशंकर के बारे में काफी बातें
लिखीं थीं। हालांकि यह किताब विवादित
भी हुई। इस किताब में पूर्व विदेश मंत्री
सुषमा स्वराज के लिए गलत शब्द का
प्रयोग किया गया था। एस जयशंकर ने
इसकी कड़ी आलोचना की थी। एस
जयशंकर ने एक दिन पहले एक निजी
टेलीवीजन न्यूज चैनल से बातचीत के
दौरान रूस संबंधों को लेकर बड़ी बातें
कहीं।
एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप
इतिहास पर नजर ढौंडाएं तो 1947 में भारत
की आजादी के बाद से सोवियत यूनियन या
रूस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे
भारत के हितों पर नकारात्मक असर पड़ा
हो। मुझे लगता है कि इस बात से कोई भी
असहमत नहीं होगा। यह बड़ा बयान है,
क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है,

जिसके लिए इन्होंने बड़ा बयान दिया जा सके। जयशंकर ने कहा कि अभी रूस की स्थिति बिल्कुल अलग है। पश्चिम के साथ रूस का संबंध पटरी से उतरा हुआ है। अभी एक ऐसा रूस है जो एशिया की ओर ज्यादा झुका हुआ है। ऐसे में हमें खुद से पूछना चाहिए कि रूस अगर एशिया की तरफ ज्यादा झुक रहा है तो एशिया में क्या उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होने चाहिए? और एक एशियाई देश के रूप में क्या हमें एशिया में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के हित में हो?

जयशंकर ने कहा कि यह साफ है कि रूस में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। दूसरी तरफ भारत को विकास के लिए इन संसाधनों की जरूरत है। लोग रूस के तेल की बात करते हैं, लेकिन बात केवल तेल की नहीं है। कोयला, उर्वरक और मेटल जैसी कई चीजें हैं। रूस के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के कई कारण हैं। जयशंकर बातचीत के दौरान ही आगे कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप यूरोशियाई भूभाग को देखें तो रूस, चीन और भारत तीन बड़े देश हैं। तीनों देशों के आपसी अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं। रूस हमारे लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक है। भारत और रूस के संबंधों को आप भरोसेमंद कर सकते हैं क्योंकि कई मौकों पर हमने यह पाया है, लेकिन चीन को आप कतार भरोसेमंद नहीं कह सकते। अब पुतिन हर्ब दोनों देशों के बीच विवाद खत्म करना चाहते हैं ताकि उनकी दुविधा भी खत्म हो जाए और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को झटका दे दिया जाए।

मारताय रज़व बफ क नए कदमः ग्रैण्डाताआ और उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा

क्या भारत आर चान के सबध 2019 जैसे नहीं होने चाहिए?

और वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नए इनिशिएटिव्स लाग करता है, जिनका उद्देश्य

ऋण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उधारकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाना होता है। हाल के वर्षों में, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न सुधार किए गए हैं, जो खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हुए हैं। इन सुधारों से न केवल ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, बल्कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में रिश्तता आई है भारत में ऋण प्रणाली में बीते कुछ दशकों में काफी बदलाव आए हैं। पहले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास अपने मानदंडों के अनुसार ब्याज दरों तय करने की स्वतंत्रता थी, जो उधारकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती थी। ऋण लेने वाले अक्सर उच्च ब्याज दरों और फोरक्लोजर या पूर्व-भुगतान पर भारी जुर्माने का सामना करते थे, जिससे समय से पहले ऋण चुकाना महंगा हो जाता था। इससे न केवल व्यक्तिगत उधारकर्ता बल्कि छोटे व्यवसाय भी प्रभावित होते थे, जो अपनी वित्तीय संरचना को सुधारने के लिए ऋण लेना चाहते थे। यह स्थिति विशेष रूप से MSME क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण थी, जो अक्सर असुरक्षित ऋणों पर निर्भर रहते हैं MSMEs के लिए इन जुर्मानों का बोझ उनकी वित्तीय योजनाको बाधित कर सकता था, जिससे वे समय से पहले अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

लिए इस स्थिति को सुधारने की पहल को इसका पहला महत्वपूर्ण कदम व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग ब्याज दर पर लिए गए ऋणों के समय से पहले भुगतान प्रलंगे वाले फोरक्लोजर शुल्क से राहत देना था। इसमें पहले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को

फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज दरों पर ऋण चुकाने के समय भारी जुर्माना चुकाना पड़ता था। यह नई नीति उधारकर्ताओं को समय से पहले ऋण चुकाने की स्वतंत्रता देती है जिससे उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों के



बहतर प्रवेशन करने में मदद मिलता है। इस पहल का दायरा अब MSME सेक्टर तक भी बढ़ा दिया गया है। यह कदम छोड़ने व्यवसायों को उनकी वित्तीय योजना का अधिक लचीला बनाने और समय से पहले ऋण भुगतान की अनुमति देता है, बिना किसी जुर्माने के। MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस तरह का सुधार इस क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करेगा। MSME क्षेत्र भारतीय GDP में महत्वपूर्ण

योगदान देता है, लेकिन यह अक्सर असुरक्षित ऋणों पर निर्भर रहता है असुरक्षित ऋण, जो संपत्ति या अन्य संसाधनों के खिलाफ लिए जाते हैं, अक्सर छोटे व्यवसायों के लिए जोखिम भरे होते हैं। इस नई नीति के तहत, MSMEs को अपने फोरक्लोजर शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे वे अपने ऋण को समय से पहले चुका सकते हैं और जुमानि से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त, MSME क्षेत्र में छोटे व्यवसाय अक्सर अपनी कैश फ्लॉप्सी में उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं। इस नई नीति से उन्हें अपनी वित्तीय योजनाएँ को अधिक सटीक तरीके से प्रबंधित करना अवश्यक हो जाएगा, जिससे वे अपने व्यापारों को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ

ही, यह उन्हें नए निवेश के अवसरों का लाभ उठाने और अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा। RBI के इन नए कदमों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और ग्राहक-केंद्रीयता को बढ़ावा देता है और उधारकर्ताओं को वित्तीय निर्णय लेने में अधिक सुरक्षा और विश्वास मिलेगा, क्योंकि अब वे यह जान सकते हैं कि उनकी ऋण अदायगी पर कोई छिपे हुए जुर्माने नहीं होंगे। इसके साथ ही, बैंक और अन्य ऋणदाता अपने ऋण उत्पादों को इस नई नीति के

प्रतिस्पृधी और ग्राहक-अनुकूल उत्पाद प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिससे ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच विश्वास बढ़ेगा। इससे बैंकिंग प्रणाली में सुधार होगा, जिससे पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि RBI का यह कदम उधारकर्ताओं के लिए अत्यधिक फायदेमंद है, लेकिन इससे ऋणदाताओं को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। समय से पहले ऋण समाप्त करने पर फोरक्लोजर शुल्क हटाने से बैंकों और NBFCs की लाभप्रदता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, बैंकों को अपने ऋण उत्पादों को अधिक कुशल और लागत-केंद्रित बनाना होगा, ताकि वे लाभ में बने रहें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ऋण

पुस्तक गर-निष्पादित संपत्ति में न बदल इसके लिए उन्हें अपने ऋण उत्पादों की संरचना में सुधार करना होगा और ऐसे ऋणों पर काम करना होगा जो निश्चित और अस्थायी दर वाले ऋणों का संयोजन हों। इससे वे न केवल उधारकर्ताओं के लिए आकर्षक विकल्प प्रदान कर सकेंगे, बल्कि अपनी लाभप्रदता भी बनाए रख सकेंगे। भारतीय रिज़िवर्बैंक के ये नए इनिशिएटिव देश की बैंकिंग और ऋण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार हैं। यह न केवल उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय राहत प्रदान करते हैं, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। खासकर MSME क्षेत्र के लिए यह कदम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें वित्तीय लचीलापन और स्थिरता प्रदान करेगा, जो उनकी विकास यात्रा के लिए

आवश्यक है। हालांकि ऋणदाताओं के लिए यह कदम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक पारदर्शी और स्थिर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है बैंकों और NBFCs को अपनी ऋण नीतियों और उत्पादों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे इस नई व्यवस्था में लाभप्रद बने रहें और उधारकर्ताओं के साथ एक स्वस्थ और संतुलित वित्तीय संबंध बनाए रख सकें।
(राजीव खरे स्टेट ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़)

ब्रिक्स शिखर सम्मलन के दोरान एक प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने घोषणा की कि भारत और चीन पूर्वी लद्धाख में एलएसी पर गश्त पैटर्न पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके तुरंत बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सुनिश्चित किया कि भारत-चीन सीमा के इस हिस्से में गश्त गलवान से पहले की अवधि में वापस आ जाएगी। अगले दिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि दोनों सरकारें पूर्वी लद्धाख में अपने मुद्दों को हल करने में सक्षम हैं। एलएसी पर जारी गतिरोध कम करने को लेकर इस विकास का भारत में कई लोगों ने विवाद किया है, जिनमें से एक ने कहा कि यह एक अवधि के दौरान भारत की स्थिति को बदल दिया जाएगा।

तत्र के लिए यह हमेशा च्छा रास्ता होता है, चीन के साथ उसके सीमा पर शांति और नए रखना हमेशा से रहा है। दोनों देशों की इस लक्ष्य पर कड़ी थी और 1990 और विशेषक में हुए कई समझौते के प्रमाण हैं। यह 2020 की गर्मियों में ल गया जब चीन की पूर्वी लद्धाख में सैन्य तीरी। इस एक कदम ने के बीच की गतिशीलता दिया है और पिछले बहाल करने के लिए पारस्परिक प्रयास करने आम भारतीय सोचेंगे कि व में इस सीमा मुद्दे के बाद हम चीन के की तरह ही व्यवहार कर आखिर, क्या विदेश मंत्री कहा था कि जब तक शांति नहीं होगी, तब तक वथ संबंधों में सामान्यता करती? परमस्या सुलझ गई है, तो और चीन के बीच संबंध में नहीं होने चाहिए?

ऐसा नहीं है। हम 2020 की बीच पिछले साढ़े चार वर्षों के साथ अपने अनुभव और वंदेज नहीं कर सकते। हरकतों के कारण दोनों बीच विश्वास गंभीर त्रप्ति हुआ है। इसे एक बार मैं आगे बढ़ाकर ही फिर जा सकता हूँ। पूर्वी पहले जो विश्वास का उपर्युक्त वापस पाने में कई भारत के मुख्य आर्थिक ने इस साल के आर्थिक चीन से भारत में अधिक शशी निवेश की अनुमति दी है।

दूसरंचार इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर रखने की जाना चाहिए। इसी तरह, जहां तक चीनी फमोटोर 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका मूल्यांकन केस-दर-केस आधार पर किया जाएगा। अगर हमने समयबद्ध तरीके से ऐसा करने के लिए पहले से ही शासन संरचनाएं स्थापित नहीं की हैं, तो हमें इसे अभी स्थापित कर लेना चाहिए। भारत में चीनी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए मुफ्त लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। इसे गांधीजी द्वारा सुझाका के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए।

मिटी चीफ

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है: IMF

नेशनल डेस्क. IMF के एशिया-प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्ण श्रीनिवासन ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रही है, जब तक कि देश के मैक्रोइकोनॉमिक मूलभूत तत्व मजबूत बने रहें। भारत स्पष्ट-24-25 में 7 प्रतिशत की बढ़िया दर बनाए रखने की उम्मीद है, जो ग्रामीण उपभोग में सुधार और फसलों की अच्छी कटाई से समर्थित है।

उन्होंने कहा कि FY24-25 में मध्यम 4.4 प्रतिशत तक गिरने की उम्मीद है, हालांकि खाद्य कीमतों में सामान्य होने के कारण कुछ उत्तर-चाहवा हो सकता है। चुनावों के बावजूद, राजकीय समेकन रास्ते पर है। रिजर्व स्थिति मजबूत है। सामान्य रूप से भारत के मैक्रोइकोनॉमिक मूलभूत तत्व मजबूत हैं।